झांसी डिफेंस कॉरिडोर की सारी बाधाएं दूर

लखनऊ। झांसी डिफेंस कॉरिडोर को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आखिरकार मंजूरी दे दी। इसी के साथ 1076 हेक्टेयर में विकसित होने वाले डिफेंस कारीडोर की सारी बाधाएं दूर हो गईं। परियोजना की कुल लागत करीब 475 करोड़ रुपये है। मालूम रहे कि झांसी नोड डिफेंस कॉरिडोर की इस सबसे बड़ी बेल्ट है, जिसमें बड़े और कोर रक्षा उत्पादों की इकाइयां लगेंगी।

पर्यावरण मंत्रालय ने दी सशर्त स्वीकृति

यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही के मुताबिक पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय ने सशर्त अनुमति दी है। ये झांसी के छह गांव और एक तहसील पर लागू होगी। पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले साल 17 अगस्त को लोक सुनवाई का आयोजन कराया था। स्थानीय लोगों की चिंताओं और समस्याओं के समाधान के बाद एनओसी मिली है। जिसके तहत प्राधिकरण परियोजना क्षेत्र के चारों ओर 15 मीटर चौड़ी घनी ग्रीन बेल्ट लगाएगा। अंदरूनी सड़कों को भी पेड़ों से आच्छादित किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र के न्यूनतम 33 फीसदी हिस्से यानी करीब 360 हेक्टेयर जमीन पर केवल हरियाली होगी। कॉरिडोर में घरेलू सीवर के लिए आठ एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यूपीडा लगाएगा। मंत्रालय द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के तहत प्रत्येक इकाई को रूफटॉप रेन पावर रिचार्ज की व्यवस्था करना होगी। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाया जाएगा। ब्यूरो